मंगलवार, 25 अगस्त, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच हुए विवाद के बाद आईसीसी ने कड़ी सजा सुनाई

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'सलार' की राधा राम मन्नार से महाकाली तक का दमदार सफर

Page-05

मोदी के लिए क्या तोहफा लेकर भारत आ रहे पुतिन? BRICS सम्मेलन से पहले दुनिया की नजर दिल्ली पर

- करीब 9 से 10 महीने के भीतर पुतिन के दोबारा भारत आने की संभावित खबर ने वैश्विक कूटनीतिक हलकों का ध्यान नई दिल्ली की ओर खींच दिया है।
- इनमें रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार, भुगतान व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग प्रमुख हो सकते हैं। अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। करीब 9 से 10 महीने के भीतर पुतिन के दोबारा भारत आने की संभावित खबर ने वैश्विक कूटनीतिक हलकों का ध्यान नई दिल्ली की ओर खींच दिया है। खासतौर पर अमेरिका और चीन की नजर इस यात्रा पर बनी हुई है, क्योंकि यह दौरा ऐसे समय में प्रस्तावित है जब भारत BRICS की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करने जा रहा है।बताया जा रहा है कि सितंबर में दिल्ली में BRICS का बड़ा सम्मेलन आयोजित होना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 12 और 13 सितंबर को राजधानी में BRICS शिखर सम्मेलन होना है। इस सम्मेलन में दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के एक मंच पर आने की उम्मीद है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को केवल एक सामान्य द्विपक्षीय दौरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।भारत और रूस के संबंध लंबे समय से रणनीतिक और बहुआयामी रहे हैं। रक्षा, ऊर्जा, परमाणु सहयोग और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच लगातार सहयोग बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ने के बावजूद भारत ने मॉस्को के साथ अपने पारंपरिक संबंधों को बनाए रखा है। इसी वजह से पुतिन का भारत दौरा पश्चिमी देशों के लिए भी खास महत्व रखता है।इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इनमें रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार, भुगतान व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग प्रमुख हो सकते हैं। इसके अलावा BRICS के भविष्य, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और डॉलर के प्रभाव जैसे मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं।पुतिन के दौरे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि रूस भारत के लिए कौन-से बड़े प्रस्ताव या समझौते लेकर आ सकता है। हालांकि किसी विशेष 'तोहफे' या बड़े समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में संभावित सहयोग पर सबकी निगाहें रहेंगी।अगर पुतिन और अन्य प्रमुख BRICS नेता सितंबर में दिल्ली पहुंचते हैं, तो यह सम्मेलन भारत की कूटनीतिक भूमिका को मजबूत करने का बड़ा अवसर बन सकता है। ऐसे में BRICS सम्मेलन से पहले पुतिन की भारत यात्रा वैश्विक राजनीति में नई तस्वीर पेश कर सकती है।

ईरान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी

'तेल की एक बूंद भी एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे', होर्मुज़ पर बढ़ा तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। ईरान ने सोमवार को अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उसके खिलाफ आर्थिक युद्ध जारी रखा गया, तो वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य से कच्चे तेल के निर्यात को पूरी तरह रोक सकता है। ईरान की इस चेतावनी ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में संभावित ऊर्जा संकट को लेकर आशंकाएं बढ़ा दी हैं।होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में शामिल है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित यह जलमार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया के कच्चे तेल के एक बड़े हिस्से की आवाजाही इसी मार्ग से होती है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का गंभीर व्यवधान अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और आपूर्ति पर सीधा असर डाल सकता है।ईरान ने अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह इस दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। तेहरान की ओर से यह संकेत दिया गया है कि यदि अमेरिका उसके खिलाफ आर्थिक कार्रवाई जारी रखता है तो वह अपनी रणनीति के तहत होर्मुज़ से तेल निर्यात को रोकने जैसे कदम उठा सकता है। ईरान की इस चेतावनी का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया और यूरोप के कई देश ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया से होने वाले तेल निर्यात पर निर्भर हैं। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए भी होर्मुज़ की स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण है।

अमरावती के NICU में भीषण आग

3 नवजातों की मौत; 36 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया

महाराष्ट्र के अमरावती शहर से सोमवार तड़के एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया। जिला महिला अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी NICU में अचानक आग लग गई। इस हादसे में तीन नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जबकि अस्पताल में मौजूद 36 अन्य नवजात बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और परिजनों में चीख़-पुकार मच गई।जानकारी के मुताबिक, आग अस्पताल की नई इमारत में स्थित NICU में लगी। इस वार्ड में समय से पहले जन्मे और गंभीर रूप से बीमार नवजात बच्चों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा जाता है। बताया गया कि तड़के करीब 3:15 बजे से 4 बजे के बीच NICU के एक हिस्से में आग फैल गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, एक वेंटिलेटर में आग लगने के बाद स्थिति बिगड़ी और देखते ही देखते धुआं पूरे हिस्से में फैलने लगा।आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल के कर्मचारियों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। राहत दल और अस्पताल कर्मियों ने मिलकर NICU में भर्ती अन्य बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान 36 नवजातों को बचाने में सफलता मिली। हालांकि, तीन बच्चों को नहीं बचाया जा सका।घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अमरावती के पुलिस आयुक्त राकेश ओला के अनुसार, हादसा सुबह करीब 3:15 से 4 बजे के बीच हुआ। आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती तौर पर वेंटिलेटर में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आग के वास्तविक कारण का पता विस्तृत जांच के बाद ही चलेगा।

तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला:

परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द, पोंगल पर 3 मुफ्त LPG सिलेंडर का ऐलान

तमिलनाडु की राजनीति और विकास योजनाओं को लेकर सोमवार को विधानसभा में कई बड़े फैसले सामने आए। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बजट सत्र के दौरान राज्य की बुनियादी सुविधाओं और जनकल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें सबसे अहम फैसला चेन्नई के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित परंदूर एयरपोर्ट परियोजना को रद्द करने का रहा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से कई नई योजनाओं का भी ऐलान किया।परंदूर में दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना लंबे समय से चर्चा में थी। हालांकि, इस योजना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा था। किसानों और स्थानीय निवासियों ने भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। व्यापक विरोध और पर्यावरणीय मुद्दों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया।मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकार विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के पक्ष में है, लेकिन स्थानीय लोगों की चिंताओं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परंदूर एयरपोर्ट परियोजना रद्द होने के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते हवाई यातायात को संभालने के लिए भविष्य में सरकार क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।वहीं, राज्य सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए पोंगल के अवसर पर तीन मुफ्त LPG सिलेंडर देने की घोषणा भी की है। इस फैसले को घरेलू बजट पर बढ़ते खर्च के बीच आम परिवारों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। रसोई गैस की कीमतों को लेकर लंबे समय से आम लोगों की चिंता बनी रहती है और सरकार की इस घोषणा का सीधा लाभ बड़ी संख्या में परिवारों को मिलने की उम्मीद है।

खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। रविवार देर रात खैबर जिले में पुलिस और फ्रंटियर कोर यानी FC की संयुक्त जांच चौकी पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में दो सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश में व्यापक अभियान शुरू कर दिया है।जानकारी के मुताबिक, आतंकवादियों ने खैबर जिले में स्थित संयुक्त जांच चौकी को निशाना बनाया। रात के समय अचानक हुए हमले से वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों को संभलने का मौका कम मिला। आतंकियों ने चौकी पर गोलीबारी की और इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।हमले में दो सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान और उनके पद से जुड़ी विस्तृत जानकारी अधिकारियों की ओर से बाद में साझा किए जाने की बात कही गई है।घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों को आशंका है कि हमला करने के बाद आतंकवादी आसपास के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में छिपे हो सकते हैं। सुरक्षाबलों ने संभावित ठिकानों पर कार्रवाई तेज कर दी है और आने-जाने वाले रास्तों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।

भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश तेज

बीजिंग पहुंचे NSA अजीत डोभाल, शी जिनपिंग के दौरे से पहले अहम बैठक

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में कूटनीतिक प्रयास एक बार फिर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे, जहां वे भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन की ओर से विदेश मंत्री और विशेष प्रतिनिधि वांग यी के शामिल होने की उम्मीद है।डोभाल की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत और चीन दोनों ही वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव कम करने और लंबे समय से चले आ रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद कई वर्षों से द्विपक्षीय संबंधों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में विशेष प्रतिनिधियों की बैठक को बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की महत्वपूर्ण कोशिश माना जा रहा है।इस वार्ता की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यह सितंबर में प्रस्तावित BRICS शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS सम्मेलन आयोजित होने की बात कही जा रही है। ऐसे में यदि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन में शामिल होते हैं, तो भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीच संभावित मुलाकात की जमीन तैयार करने में यह वार्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि, शी जिनपिंग के भारत दौरे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद दोनों देशों के अधिकारियों के स्तर पर उनके सम्मेलन में शामिल होने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए जा रहे हैं। ऐसे में डोभाल की बीजिंग यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में आगे की दिशा तय करने वाली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।भारत की प्राथमिकताओं में LAC पर शांति और स्थिरता के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिकों के बीच तनाव को कम करना प्रमुख मुद्दा है। भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि सीमा पर शांति और सामान्य स्थिति के बिना दोनों देशों के व्यापक संबंधों में स्थायी सुधार मुश्किल होगा। दूसरी ओर, चीन के साथ व्यापार, आर्थिक संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। विशेषज्ञों की नजर इस बात पर होगी कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से सीमा विवाद को लेकर कोई ठोस प्रगति होती है या नहीं।

ईरान को 'मक्का रक्षा समझौते' में शामिल होने का न्योता?

सऊदी-पाक-तुर्की गठजोड़ से बदलेगा मिडिल ईस्ट का समीकरण

ईरानी संसद से जुड़े एक अधिकारी के दावे ने सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के संभावित सैन्य गठजोड़ को लेकर नई हलचल पैदा कर दी है।दावा है कि ईरान को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है, हालांकि संबंधित देशों की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह गठजोड़ वास्तविक रूप लेता है, तो इससे मध्य पूर्व की रणनीतिक राजनीति और अमेरिका-इजरायल के क्षेत्रीय समीकरणों पर बड़ा असर पड़ सकता है।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

दो सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब और ईरान अब एक ही सैन्य छाते के नीचे आने वाले हैं? क्या अमेरिका और इसराइल को घेरने के लिए मुस्लिम देशों का एक ऐसा अमेद्य किला तैयार हो रहा है जिसकी कमान पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी और ईरान के हाथों में होगी? ईरान की संसदीय समाचार एजेंसी खाना मिल्लत के प्रमुख मेहंदी रहीमी ने अलमयादीन को एक दिए इंटरव्यू में यह कहकर सनसनी फैला दी कि ईरान को मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है। तेहरान इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में स्पष्ट नियम है। अगर एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। ईरानी संसद की मीडिया विंग के प्रमुख मेहंदी रहीमी ने दावा किया है कि तीनों देशों ने ईरान को भी इस ऐतिहासिक गुट में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा है। रहीमी के मुताबिक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी ढांचा खड़ा होना ईरान की कूटनीतिक जीत है। हालांकि अभी तक ना तो ईरानी विदेश मंत्रालय और ना ही सऊदी, तुर्की या पाकिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने इस न्योते को औपचारिक पुष्टि की है। ऐसे में अगर यह दावा सच साबित हो गया तो तेहरान इस ब्लॉक में शामिल होता है तो मध्य पूर्व के तमाम पुराने समीकरण एक बार में ही ध्वस्त हो जाएंगे। दशकों तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे सऊदी अरब और ईरान का एक रक्षा मंच पर आना अमेरिका और इसराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। तुर्की पहले ही साफ कर चुका है कि वह यह समझौता पूरी तरह रक्षात्मक और किसी देश के खिलाफ नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की परमाणु ताकत, तुर्की की आधुनिक सेना, सऊदी की वित्तीय शक्ति और ईरान की मिसाइल क्षमता एक साथ आती है तो इसराइल की रणनीतिक घेराबंदी पूरी तरह पस्त हो जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि जो तीनों देश अमेरिका के मित्र देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान, सऊदी या फिर तुर्की हो। वो क्या ईरान जैसे दुश्मन को अपने गुट में शामिल करेंगे? एक तरफ पाकिस्तान खुद को इस्लामिक नाटो का मुख्य रणनीतिकार पिलर बताकर शेखी बगारने में लगा है। दूसरी तरफ खाड़ी देशों में उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हाल ही में मार्च से जुलाई के बीच छह खाड़ी देशों ने 20,000 से अधिक पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट कर दिया है। पाकिस्तान नागरिकों पर भीख मांगने, ओवरस्टे करने और अपराधों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं। एक तरफ पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य साख चमकाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसके नागरिकों के साथ खाड़ी देशों का यह सलूक इस्लामाबाद के लिए अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बन चुका है। ईरान के इस नए सैन्य ब्लॉक में एंट्री अगर हकीकत बनती है तो यह अमेरिका के एक क्षेत्र प्रभाव को खत्म कर सकता है और एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा युग की शुरूआत करेगी। अब देखना यह हो जाता है कि रियाद और वाशिंगटन इस दावे पर क्या आधिकारिक रुख अपनाते हैं या फिर अंकारा या इस्लामाबाद की ओर से क्या इस पर कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाएगा।

तेजस Mk2 के सामने नहीं टिक पाएगा चीनी JF-17 लड़ाकू विमान

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाकू विमानों को लेकर हमेशा से दिलचस्प मुकाबला रहा है। पाकिस्तान भले आर्थिक संकट में फंसा रहा हो लेकिन उसके पास एडवांस लड़ाकू विमान हमेशा से रहे हैं। इस बीच तेजस-2 को लेकर पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसके सामने पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि रडार या मिसाइल रेंज को लेकर बहस बेकार है बल्कि असल में B V R (Beyond-Visual-Range) मिसाइल तेजस एमके 2 को JF-17 के मुकाबले ज्यादा खतरनाक विमान बनाता है। आपको बता दें कि अमेरिकी GE F414 शक्तिशाली इंजन और 11 हार्डपॉइंट्स जहां मिसाइल लगाए जाएंगे उनसे लैस तेजस Mk2 एक 'मीडियम-वेट' फाइटर के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। यह युद्ध की स्थिति में JF-17 ब्लॉक 3 की तुलना में ज्यादा BVR मिसाइलें और ईंधन ले जाने में सक्षम होगा। हालांकि पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 चीनी PL-15E मिसाइलों से लैस एक सस्ता 4.5 जनरेशन जेट है लेकिन पाकिस्तानी विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च-तीव्रता वाले हवाई युद्ध में तेजस Mk2 की बहुमुखी प्रतिभा और मारक क्षमता के आगे जेएफ 17 का टिकना बेहद मुश्किल होगा। पाकिस्तानी एनालिस्ट का कहना है कि एक साफ अंतर एयरक्राफ्ट की 'बियॉन्ड-विजुअल-रेंज' (BVR) मिसाइल ले जाने की क्षमता है। JF-17 Block III को चार PL-15 BVR मिसाइलें ले जाते हुए सार्वजनिक रूप से दिखाया गया है। मई 2025 में 'जेन्स' ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान एयर फोर्स की आधिकारिक तस्वीरों में JF-17 Block III को चार PL-15 मिसाइलें ले जाते हुए दिखाया गया था जिनमें P L - 1 0 E शॉर्ट-रेंज मिसाइलें शामिल हैं, लेकिन चार बड़े BVR हथियार सबसे ज्यादा दिखाए जाने वाले भारी BVR कॉन्फिगरेशन हैं।

गैर मराठी ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक पर अब RTO के खिलाफ सड़क पर उतर आए

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महाराष्ट्र में गैर-मराठी ऑटो रिक्शा-टैक्सी चालक RTO की कार्रवाई के खिलाफ विरोध पर उतर आए हैं। कुर्ला में रिक्शा चालकों ने काम बंद करने का आंदोलन शुरू कर दिया है। गैर-मराठी ऑटो रिक्शा-टैक्सी चालकों ने आरोप लगाया कि सरकार की इस पूरी कार्रवाई के पीछे राजनीति की जा रही है।महाराष्ट्र में गैर-मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ RTO की मुहिम जारी है। महाराष्ट्र में जिन चालकों को मराठी भाषा नहीं आती, उन्हें पहले एक महीने का नोटिस दिया जा रहा है। एक महीने में मराठी नहीं सीखने पर उनके बैज रद्द करने की प्रक्रिया के तहत तीन महीने का नोटिस दिया जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में चालकों ने काम बंद कर विरोध शुरू कर दिया है। मुंबई के कुर्ला में बड़ी संख्या में रिक्शा चालक सड़क पर उतर आए हैं। सैकड़ों रिक्शाएं कतार में खड़ी हैं और चालकों ने अपना काम बंद कर दिया है। रिक्शा चालकों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। रिक्शा चालकों का कहना है कि उन्हें मराठी सीखने में कोई परेशानी नहीं है। वे मराठी सीख भी रहे हैं, लेकिन सरकार को उन्हें कम से कम छह महीने का समय देना चाहिए, ताकि वे मराठी भाषा को ठीक से सीख सकें और बोल सकें। चालकों का कहना है कि जब वे मराठी बोलने की कोशिश करते हैं तो कई बार ग्राहक उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई में उनका समय भी जाता है और जुर्माना लगने से आर्थिक नुकसान भी होता है। रिक्शा चालकों का सवाल है कि कार्रवाई सिर्फ गरीब रिक्शा और टैक्सी चालकों के खिलाफ ही क्यों की जा रही है? जो लोग पिछले कई दशकों से मुंबई में रिक्शा और टैक्सी चला रहे हैं। उनके खिलाफ अचानक इस तरह का अभियान क्यों शुरू किया गया है? चालकों का आरोप है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे राजनीति है। गरीब रिक्शा-टैक्सी चालकों को निशाना बनाया जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार मराठी सीखने के लिए दी जा रही समय-सीमा को बढ़ाए।

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध पर मोहसिन रेजाई ने दिया बड़ा बयान

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े युद्ध को लेकर दोनों ओर से बयानबाजी हो रही है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए प्रमुख मोहसिन रेजाई ने रविवार को चेतावनी दी है। रेजाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को 'युद्ध' माना जाएगा। वहीं, ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन का बचाव किया। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कट्टरपंथी नेता मोहसिन रेजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह चेतावनी दी। उन्होंने सरकारी प्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा, 'अगर (डोनाल्ड ट्रंप) कुछ करना चाहते हैं, तो हम भी मुंह तोड़ पलटवार करेंगे।' दूसरी ओर, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट सोमवार को ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच, मध्यस्थों के जरिए वार्ता फिर शुरू कराने के प्रयासों के तहत पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी सोमवार को ईरान की यात्रा कर सकते हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने अपनी खबर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर सोमवार को तेहरान पहुंचेंगे और एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बीच, होर्मुज स्ट्रेट में हमलों में कमी आई है, लेकिन दोनों पक्षों की बयानबाजी जारी है। हाल ही में गठित एक ईरानी प्राधिकरण ने ढेरों ऐसे जहाजों की सूची जारी की है, जिन्हें भविष्य में इस मार्ग से गुजरने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति असद के वफादार पूर्व ग्रैंड मुफ्ती पर गिरी गाज

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

सीरिया के दमिश्क स्थित चौथी आपराधिक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासनकाल के दौरान देश के ग्रैंड मुफ्ती रहे अहमद बदरुद्दीन हसून (A h m a d Badreddin Hassoun) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हसून को हिंसा भड़काने, सांप्रदायिक कलह पैदा करने और असद शासन के अपराधों को धार्मिक व नैतिक वैधता प्रदान करने का दोषी पाया गया।दमिश्क की चौथी आपराधिक अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने हसून को हिंसा भड़काने, हत्याओं को सही ठहराने और अपने पद का दुरुपयोग करने समेत कई अपराधों का दोषी पाया। हसून ने 2005 से 2021 के बीच सीरिया के ग्रैंड मुफ्ती के रूप में कार्य किया। उन्हें मार्च 2025 में दमिश्क हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। हसून एक महीने पहले ही अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आए थे। उनके खिलाफ मुकदमा 25 जून को शुरू हुआ था। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के तहत उनका आपराधिक मुकदमा 25 जून 2026 को शुरू हुआ था। अभियोजकों ने सुनवाई के दौरान हसून के लिए मृत्युदंड (फांसी की सजा) की मांग की थी, जिसे अदालत ने बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया। अहमद बदरुद्दीन हसून ने वर्ष 2005 से 2021 तक सीरिया के शीर्ष मुस्लिम धर्मगुरु (ग्रैंड मुफ्ती) के रूप में कार्य किया था। बशर अल-असद की सरकार के पतन के बाद वे अज्ञात स्थान पर छिपे रहे। खुफिया सूचना के आधार पर हसून को मार्च 2025 में दमिश्क हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। अहमद बदरुद्दीन हसून को सीरिया के लगभग 14 साल लंबे युद्ध के दौरान किए गए अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अहमद बदरुद्दीन हसून (Ahmad Badr al-Din Hassoun) एक प्रमुख सीरियाई इस्लामी विद्वान हैं, जिन्होंने वर्ष 2005 से 2021 तक सीरिया के ग्रैंड मुफ्ती (Grand Mufti) के रूप में कार्य किया। वे पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद की सरकार के करीबी और वफादार माने जाते रहे हैं। उन्होंने 2005 में शेख अहमद कुफ्तारो के निधन के बाद सीरिया के ग्रैंड मुफ्ती का पद संभाला था, जो 2021 तक रहा। वे अंतरधार्मिक संवाद (Interfaith dialogue) के समर्थक और सेकुलर शासन प्रणाली के पैरोकार के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने 1990 से 1998 तक सीरिया की पीपुल्स असेंबली (संसद) के सदस्य के रूप में भी सेवा दी।

संपादक की कलम से

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता चुनने की प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद हैं। ऐसे में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव देश की चुनावी व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना पैदा करता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का हरिद्वार में संत समाज के सामने इस व्यवस्था का समर्थन और इसे विकसित भारत के लिए जरूरी बताना इस बहस को फिर राजनीतिक केंद्र में ले आया है।एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि बार-बार होने वाले चुनावों से सरकारी मशीनरी और प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कई विकास कार्यों और नई योजनाओं पर अस्थायी रोक लग जाती है। राजनीतिक दलों को लगातार चुनावी तैयारियों में जुटे रहना पड़ता है और सरकारी कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या चुनावी ड्यूटी में लगती है। यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों की बचत संभव हो सकती है।लेकिन इस प्रस्ताव के सामने कई गंभीर संवैधानिक और व्यावहारिक प्रश्न भी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अलग-अलग राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल कैसे समायोजित किया जाएगा। यदि 2029 में एक साथ चुनाव कराने का लक्ष्य रखा जाता है तो कई राज्यों में निर्धारित समय से पहले चुनाव कराने की जरूरत पड़ सकती है। इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या जनता द्वारा चुनी गई सरकारों का कार्यकाल राजनीतिक सुविधा के लिए कम किया जाना उचित होगा।दूसरी चुनौती राजनीतिक सहमति की है। भारत में केंद्र और राज्यों की सरकारें अलग-अलग जनादेश के आधार पर चुनी जाती हैं। कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा में अलग-अलग दलों को समर्थन देते हैं। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था कहीं राज्यों के मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों के पीछे दबा न दे, यह चिंता भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय दलों को आशंका है कि संसाधनों और प्रचार के मामले में राष्ट्रीय दलों का प्रभाव बढ़ सकता है और स्थानीय मुद्दों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाएगी।भारत में एक साथ चुनाव कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। बाद में कुछ राज्यों की विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने और राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने के कारण चुनावों का चक्र अलग-अलग हो गया। इसलिए इतिहास यह बताता है कि व्यवस्था संभव है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।'वन नेशन, वन इलेक्शन' को केवल चुनाव खर्च घटाने के नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए व्यापक संवैधानिक सहमति, राज्यों का विश्वास, राजनीतिक दलों की भागीदारी और स्पष्ट कानूनी व्यवस्था जरूरी है। लोकतंत्र में सुधार तभी सफल माना जाएगा जब उससे चुनावी प्रक्रिया सरल होने के साथ-साथ जनता के अधिकार और राज्यों की स्वायत्तता भी सुरक्षित रहे।

Gen-Z को साधने की नई सियासी रणनीति भाषण से ज्यादा संवाद और म्यूजिक पर जोर

कांग्रेस का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम राजनीति में Gen-Z से संवाद के बदलते तरीके की तस्वीर पेश कर रहा है।राहुल गांधी के कार्यक्रमों में छात्रों के सवाल, म्यूजिक, सोशल मीडिया और सीधे संवाद को प्राथमिकता दी जा रही है।दुनिया भर में युवा राजनीति के बदलते तौर-तरीकों के बीच पार्टियां अब युवाओं को सिर्फ श्रोता नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार बनाने पर जोर दे रही हैं।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

सियासत में नई पीढ़ी से संवाद का तरीका बदल रहा है। खासकर Gen-Z को जोड़ने के लिए अब पारंपरिक मंच, लंबे भाषण और एकतरफा संवाद के बजाय ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें युवा खुद कार्यक्रम का हिस्सा महसूस करे। कांग्रेस किन'छात्रों की गूंज' में यह बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने के लिए मंच पर जरूर हैं, लेकिन फोकस छात्रों की बात सुनने पर है। दरअसल, यह बदलाव उस समय हो रहा है जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जेन जी के राजनीतिक आंदोलनों ने पारंपरिक राजनीतिक संचार को चुनौती दी है। युवाओं के आंदोलनों में सोशल मीडिया, मीम, संगीत और पॉप-कल्चर महत्वपूर्ण माध्यम बने हैं। यही वजह है कि नए फॉर्मूले में छात्रों के सवाल, सीधे संवाद, हाथ मिलाना, सेल्फी, हाथ लहराना, शोर-शराबा और म्यूजिक को मिलाकर एक इवेंट बनाया जा रहा है। पुणे और इससे पहले कोटा, प्रयागराज व देहरादून में 'छात्रों की गूंज' के दौरान जेन जी को जोड़ने के लिए म्यूजिक और कॉन्सर्ट का इस्तेमाल भी इसी बदलाव की ओर इशारा करता है। जेन जी के लिए राजनीति का पारंपरिक दृश्य मंच पर नेता, सामने भीड़ और नेता का लंबा भाषण की बजाय कार्यक्रम का पूरा माहौल ऐसा बनाने की कोशिश है, जिसमें युवा केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि इवेंट का एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। इसीलिए 'छात्रों की गूंज' में शामिल होने वालों के लिए कुर्सियां भी नहीं लगाई जा रही है। करीब तीन से चार घंटे छात्र छात्राओं के खड़े होकर जोश में नारे लगाना, गानों पर झूमना, हाथ लहराना एक अलग ही तरह का रोमांच पैदा करता दिखाई देता है। बाद में सियासी और सामाजिक सवाल और जवाब पर खुद को शामिल कर देश के मुद्दों से जुड़ा होने का इजहार भी करते दिखते हैं। यह बदलाव केवल मैदान में नहीं है। सोशल मीडिया पर भी संवाद का तरीका बदला है। राहुल गांधी ने 6 अगस्त को इंस्टाग्राम पर छात्रों और जेन जी से सीधे कहा, आई एम हेयर टू लिसन, आस्क मी एनीथिंग। यानी मंच पर मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए के बजाय सोशल मीडिया पर 'आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा' का फॉर्मूला अपनाया गया। अमेरिका में टाउन हॉल की पुरानी संस्कृति अब जेन जी को ध्यान में रखकर नया रूप ले रही है। ब्रिज एलायंस ने जुलाई 2026 में जेन जी टाउन हॉल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे संगठन ने एक नए तरह का नागरिक संवाद और लाइव ऑनलाइन टाउन हॉल बताया है। इसमें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसद एक साथ युवाओं के सवालों पर बातचीत करते हैं। दोनों नेताओं को बराबर बोलने का समय मिलता है, जबकि सवाल युवा मॉडरेटरों की प्रक्रिया से चुने जाते हैं। यानी मंच पर नेता का एकतरफा भाषण नहीं, बल्कि युवाओं के सवालों से बातचीत की दिशा तय होती है। पहला कार्यक्रम 21 जुलाई 2026 को निर्धारित किया गया था। यह दिखाता है कि पारंपरिक टाउन हॉल भी अब युवा-केंद्रित, संवादात्मक और डिजिटल फॉर्मेट की ओर बढ़ रहा है। ब्रिटेन और यूरोप में राजनीति और पॉप-कल्चर का रिश्ता नया नहीं है। चुनावी अभियानों में संगीत, लोकप्रिय संस्कृति और युवाओं की भाषा का इस्तेमाल लंबे समय से होता रहा है। लोकप्रिय कलाकारों और गीतों का इस्तेमाल मतदाताओं, खासकर युवाओं तक पहुंचने के लिए किया गया है।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर तेज हुई हलचल, 2029 में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी के संकेत

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हरिद्वार में संतों की बैठक में 'एक देश, एक चुनाव' का समर्थन किया और बार-बार होने वाले चुनावों को देश के विकास में बाधा बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने संत समुदाय से इस संवैधानिक सुधार के समर्थन में जन जागरूकता पैदा करने में मदद करने की अपील की। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंच पर उपस्थित थे और उन्होंने शिवराज सिंह के साथ इस पहल के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। शिवराज सिंह ने कहा, "बार-बार होने वाले चुनाव विकास और जनसेवा की गति को प्रभावित करते हैं, जिससे समय, धन और प्रशासनिक संसाधनों का भारी नुकसान होता है।" बता दें कि हरिद्वार में संत समाज के समागम में वन नेशन वन इलेक्शन पर संकल्प के बाद अब सबसे बड़ी सुगबुगाहट हुई है। 2029 में लोकसभा और 22 राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि 2034 में नहीं बल्कि 2029 में ही मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराने के मूड में है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। जिन 22 राज्यों में ये चुनाव होने हैं उसमें अभी 16 राज्यों में NDA की सरकार है जबकि 6 राज्यों में इंडी अलायंस की सरकार है। हालांकि इसके लिए यूपी, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब,हिमाचल,मणिपुर में 3 साल पहले चुनाव कराना होगा क्योंकि इन राज्यों में 2027 में चुनाव हैं जो 5 साल यानि 2032 तक वैलिड है। अगर 2029 में चुनाव कराना है तो 3 साल पहले कराना होगा।वहीं, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, नागालैंड,छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान,त्रिपुरा में 4 साल पहले चुनाव कराना होगा क्योंकि यहां 2028 में चुनाव हैं जो 5 साल यानि 2033 तक वैलिड है। यानि 4 साल पहले चुनाव कराना होगा। भारत के लिए यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। इस बीच, दिल्ली से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन संबंधी विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की मीटिंग चल रही है जिसमें प्रियंका गांधी, पी, चिदबंरम, सुरजेवाला समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने के लिए एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी पहुंची हैं।

बीजेपी के पूर्व नेता आरके सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार से सवाल किए

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

बीजेपी के पूर्व नेता आरके सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित घुसपैठ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर सरकार से सीमा पर चीनी गतिविधियों को लेकर सीधे जवाब देने की मांग की है। आरके सिंह ने कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के करीब 60 किलोमीटर अंदर तक आ गई है। उन्होंने दावा किया कि एक पेट्रोलिंग पॉइंट सेरा-5 तक पहले भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टियां नियमित रूप से जाती थीं। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी का चीनी सेना की पेट्रोलिंग पार्टी से आमना-सामना हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने वहां पेट्रोलिंग बंद कर दी और अब कथित तौर पर उस इलाके में चीनी सेना का कब्जा हो गया है। आरके सिंह के मुताबिक, वहां भारतीय सेना की ओर से बनाए गए कुछ ढांचों को भी तोड़ दिया गया है। आरके सिंह ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या यह सही है कि सेरा-5 पर चीनी सेना ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने यह भी पूछा कि भारत-चीन सीमा पर ऐसे कितने पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, जहां पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अब वहां जाना बंद हो गया है। साथ ही उन्होंने सरकार से पूछा कि इनमें से कितने पेट्रोलिंग पॉइंट पर चीनी सेना का कब्जा हो चुका है। पूर्व बीजेपी नेता ने एक मंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि चीनी सेना के भारतीय सीमा के अंदर आने की बात कहना गलत है, क्योंकि सीमा का स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं हुआ है। आरके सिंह ने कहा कि मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि पहले सीमा तक सड़कें नहीं बनाई जाती थीं, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में सीमावर्ती इलाकों तक सड़क निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि गांव वालों की ओर से कही जा रही बातों को आपसी मुद्दा बताकर खारिज किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए पेट्रोलिंग पॉइंट के सवाल का सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। आरके सिंह ने कहा कि पेट्रोलिंग पॉइंट से जुड़ी जानकारी को महज फेक न्यूज कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। सरकार को इस मुद्दे पर सीधे-सीधे जवाब देना चाहिए और अगर कहीं गलती हुई है तो उसे सुधारना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देश की सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। ऐसे मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने यह सवाल उठाया है, ताकि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, वे समझें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है।

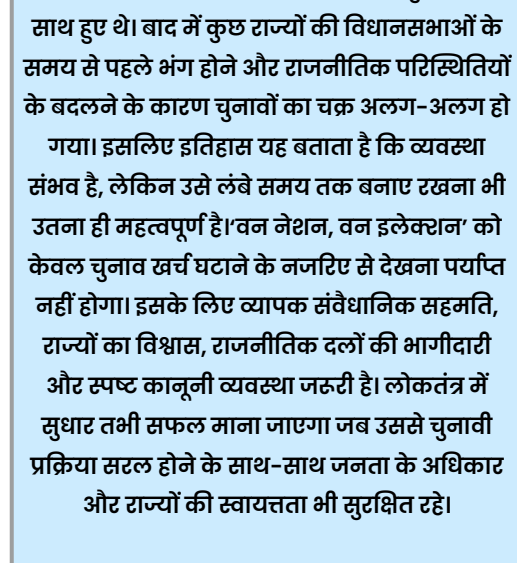

HURL में सरकारी नौकरी का शानदार मौका

एग्जीक्यूटिव समेत कई पदों पर भर्ती; ₹1.80 लाख तक सैलरी

सरकारी कंपनी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (HURL) कंपनी ने एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकली हैं। एमबीबीस कर चुके उम्मीदवारों को भी इस भर्ती में अच्छी सैलरी वाली नौकरी लेने का चांस मिल रहा है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट jobse4.hurl.net.in पर चल रही है। फॉर्म भरने में ज्यादा देर ना करें क्योंकि लास्ट डेट बिल्कुल नजदीक है। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (HURL) भारत की प्रमुख सरकारी क्षेत्र की उर्वरक बनाने वाली कंपनी है। यह CIL, NTPC, IOCL, FCIL और HFCL का ज्वाइंट वेंचर है। जिसे अनुभवी और योग्य उम्मीदवारों की तलाश है। इस भर्ती के माध्यम से प्रोसेस इंजीनियरिंग, यूरिया, अमोनिया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग और मेडिकल जैसे डिसिप्लीन में कैंडिडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। सभी के लिए योग्यता और उम्र संबंधित नियम भी अलग-अलग तय किए गए हैं। HURL में जॉइनिंग के बाद उम्मीदवारों को पोस्ट वाइज सैलरी मिलेगी। यह कैडर के अनुसार होगी। एग्जीक्यूटिव कैडर में असिस्टेंट मैनेजर E-2 ग्रेड पर ₹50000-₹160000/- प्रति माह तक सैलरी मिलेगी। वहीं E-1 A सीनियर इंजीनिय/सीनियर ऑफिसर को ₹45000-₹150000, E-1 इंजीनियर/ऑफिसर को ₹40000-₹140000 तक वेतन मिलेगा। नॉन एग्जीक्यूटिव L0 ग्रेड पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट (II) ग्रेड-2 पर ₹25000-₹86400/- तक मंथली सैलरी मिलेगी। फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रेक्ट (FTC) बेस पर भी सभी का वेतन अलग-अलग निर्धारित किया गया है। ऑफिसर को ₹40000-₹140000, असिस्टेंट मैनेजर को ₹50000-₹160000 और डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर ₹60000-₹180000 वेतन तय किया गया है। एचयूआरएल की इस नई भर्ती में योग्य अभ्यर्थी अंतिम तिथि 26 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन एप्लिकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट jobse4.hurl.net.in पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। इसके लिए आपको संबंधित भर्ती के विज्ञापन पर जाकर Click to register के लिंकपर जाना होगा।

अब अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस में शहर, जिला, राज्य, पिनकोड की जानकारी भरें। इसके बाद Save& Next पर क्लिक करके अन्य जानकारी भरें। बेसिक जानकारी भरने के बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, अनुभव और योग्यता संबंधित जानकारी भरने के बाद फॉर्म की प्रिव्यू करें और फाइनल सबमिट कर दें। फोटो, हस्ताक्षर अधिकतम 1 MB में jpg/jpeg फॉर्मेट में अपलोड करें।

अन्य डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट भी निकाल लें।ऑनलाइन आवेदन 26 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक चालू रहेंगे। इसके बाद एप्लिकेशन विंडो बंद हो जाएगी। भर्ती से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी एचयूआरएल की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1000 से ज्यादा इंटर्नशिप सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए

कॉलेज की पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप काम सीखने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। इसके जरिए कैंडिडेट्स को प्रैक्टिल नॉलेज के साथ काम की दुनिया का असल अनुभव हासिल का अवसर मिलता है। जो कैंडिडेट्स ऐसी ही मौके की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए NHAI खुशखबरी लेकर आया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026-27 और टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की प्रतिष्ठित संस्था है, जो देश के नेशनल हाईवे के विकास, रखरखाव और उनसे जुड़े सभी तरह के प्रबंधन का काम करती है। यह मौका खासतौर से उन छात्रों के लिए है, जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रोड सेफ्टी, मैनेजमेंट, लॉ और फाइनेंस, मीडिया, इनफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। देशभर में चल रहे 125 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर कैंडिडेट्स काम कर सकेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेने के साथ कैंडिडेट्स को हर महीने अच्छा स्टाइपेंड भी आपका यूनिवर्सिटी कॉर्डिनेटर आपके एप्लिकेशन का रिव्यू करेगा। इसके बाद उनके द्वारा रिकमेंड होने के बाद NHAI का एडमिन आवेदन पत्र में से कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। जो अभ्यर्थी चुने जाएंगे, उन्हें ईमेल या एसएमएस के जरिए ऑफर लेटर भेजे जाएंगे। इंटर्नशिप के लिए अभ्यर्थियों को एनएचएआई की प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद रहना होगा। यहीं आपको सीनियर कर्मचारियों के मार्गदर्शन में काम करना होगा। विंटर इंटर्नशिप दिसंबर से जनवरी केवल एक महीने होती है। लेकिन टर्म इंटर्नशिप 6 महीने की होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1000 से ज्यादा इंटर्नशिप सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किए हैं। स्टूडेंट्स जो पेड इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, उनके लिए अच्छा चांस हैं।

आर प्रज्ञाननंदा ग्रैंड चेस टूर फाइनल में जगह बनाने के करीब

साउथ अफ्रीका की टीम 28 अगस्त से नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ मिलकर ट्राई सीरीज खेलेगी

28 अगस्त से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के बीच टी20 ट्राई सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के शुरू होने से पहले साउथ अफ्रीकी टीम को एक बड़ा झटका लगा है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जेसन स्मिथ जो 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफ्रीकी टीम का हिस्सा थे, वो इस ट्राई सीरीज से बाहर हो गए हैं। हालांकि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अभी तक उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है। वह मांसपेशियों में खिंचाव यानी 'एडक्टर मसल स्ट्रेन' की वजह से इस सीरीज से बाहर हुए हैं। साउथ अफ्रीका के लिए 11 T20I और 3 वनडे खेल चुके जेसन स्मिथ इस ट्राई सीरीज के लिए अफ्रीकी टीम का अहम हिस्सा थे। सेलेक्टर्स ने इस सीरीज के लिए कई नए और युवा प्लेयर्स को मौका दिया है, जिनमें स्मिथ थोड़े अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं। फिलहाल उनकी चोट की जांच की जाएगी, जिसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि वह 9 सितंबर से शुरू होने वाली वनडे (ODI) सीरीज में खेल सकेंगे या नहीं। जेसन स्मिथ के T20I आंकड़े की बात करें तो उन्हें अभी तक 11 मैचों में खेलने का मौका मिला है। वहां वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अब तक 10 पारियों में 20.66 की औसत से 124 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 119.23 का रहा है। इस फॉर्मेट में वह एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। हाल के दिनों में चोटिल होने वाले साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों में स्मिथ तीसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले कगिसो रबाडा की हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी और सेनुरन मुथुसामी कमर में जकड़न की वजह से बांग्लादेश 'ए' के खिलाफ साउथ अफ्रीका 'ए' टीम के लिए नहीं खेल पाए थे। नामीबिया सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम 25 अगस्त को विंडहोक के लिए रवाना होगी। सीरीज का पहला मैच 28 अगस्त को नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा।

आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को मंज़ूरी

जापान के आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को शनिवार को युवा मामले और खेल मंत्रालय से प्रशासनिक और वित्तीय मंज़ूरी मिल गई है; इन खेलों में 35 अलग-अलग खेलों में 492 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। मंज़ूरी पाने वाले इस दल में 265 पुरुष और 227 महिला एथलीट शामिल हैं। यह मंज़ूरी भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के अनुरोध पर दी गई है, जिसने इस महीने की शुरुआत में एक पत्र और बाद की बातचीत के ज़रिए सरकार से मंज़ूरी मांगी थी।एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा 73 भारतीय एथलीट हिस्सा लेंगे, इसके बाद हॉकी में 40 और शूटिंग व क्रिकेट में 30 एथलीट शामिल होंगे। भारत तीरंदाज़ी, कबड्डी और बैडमिंटन जैसे खेलों में भी अपनी टीमें उतारेगा। साथ ही, एथलीटों को मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ई-स्पोर्ट्स और टेकबॉल जैसे नए उभरते खेलों में भी हिस्सा लेने की मंज़ूरी दी गई है। कोच, सपोर्ट स्टाफ़, मेडिकल स्टाफ़ और दल के अधिकारियों सहित टीम के अधिकारियों के लिए मंज़ूरी अलग से जारी की जाएगी।क्रिकेट में कुल 30 खिलाड़ी हैं – पुरुषों और महिलाओं की टीमों में 15-15 खिलाड़ी। पुरुषों की टीम में युवा वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या नहीं हैं। महिलाओं की टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेंगी। डोपिंग की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान कुश्ती और वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों को हुआ है। असल में, पता चला है कि वेटलिफ्टर्स की शुरुआती लिस्ट में करीब 10 खिलाड़ी थे, जिसे घटाकर अब सिर्फ़ पांच कर दिया गया है। कुश्ती में भी हाल ही में एक रेसलर के टेस्ट में पॉज़िटिव पाए जाने के बाद कुछ नाम हटा दिए गए हैं।

यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच हुए विवाद के बाद आईसीसी ने कड़ी सजा सुनाई

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है। इस टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच टकराव और तीखी झड़प देखने को मिली थी। इस विवाद पर सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने कड़ा एक्शन लिया है। दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.12 को तोड़ने का दोषी पाया गया है। इसके चलते इन दोनों पर मैच फीस का 25-25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही दोनों के खाते में एक-एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है। दोनों खिलाड़ियों की पिछले 24 महीने में ये पहली गलती है। इसलिए कम सजा मिली है।दरअसल, यह घटना भारत की पहली पारी में पहले दिन रविवार को 17वें ओवर में हुई, जब असिथा फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया। भारत बल्लेबाज फर्नांडो की ओर बढ़ा और इस दौरान दोनों के बीच काफी तीखी नोक-झोंक हुई। इसके बाद बाद फर्नांडो ने अपना सिर जायसवाल की ओर बढ़ाया। इसके जवाब में जायसवाल झुके, जिससे दोनों के सिर आपस में टकरा गए। यह देख श्रीलंका के अन्य खिलाड़ियों असिथा को अलग खींचते हुए विवाद को शांत कराया। आईसीसी के प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.12 के तहत दोषी पाया गया है। ये नियम किसी प्लेयर, प्लेयर सपोर्ट स्टाफ, अंपायर, मैच रेफरी या किसी दूसरे व्यक्ति (इंटरनेशनल मैच के दौरान दर्शक समेत) के साथ गलत फिजिकल कॉन्टैक्ट से जुड़ा है। इसके तहत पहले बार अपराध करने पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना और एक-एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया। दोनों खिलाड़ियों का पिछले 24 महीने में यह पहला अपराध था, इसलिए कम सजा दी गई है।

ट्रेन का वेंडर, 19 भाषाओं का मास्टर

ट्रेन में सफर करते समय अक्सर अलग-अलग तरह के वेंडर दिखाई देते हैं. कोई चाय बेचता है, कोई पानी तो कोई खाने-पीने या रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान. ज्यादातर लोग उन्हें देखकर सामान खरीदते हैं और फिर अपने सफर में व्यस्त हो जाते हैं. लेकिन एक ट्रेन में यात्रियों की मुलाकात ऐसे वेंडर से हुई, जिसने अपने सामान से ज्यादा अपने हुनर से सबको हैरान कर दिया.

दावा है कि उन्होंने कटट क्रिएशन से तीन साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा

पिता-बेटी ने खाना चखा तो भर आईं आंखें

5 साल तक फ्रीजर में रखी मां के हाथ की डिश

किसी अपने के जाने के बाद उसकी यादों को संभालकर रखना इंसान के लिए बेहद भावुक अनुभव होता है. कोई तस्वीरों में अपने पसंदीदा लोगों को तलाशता है, कोई उनके कपड़ों को संभालकर रखता है तो कोई उनकी पसंदीदा चीजों को यादों के तौर पर सहेज लेता है.

लेकिन जापान से सामने आई एक कहानी ऐसी है, जहां एक बेटी अपनी दिवंगत मां की आखिरी याद उनके हाथों से बने खाने पूरे पांच को पूरे पांच साल तक संभालकर रखा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जापान की मिजुकी तकाराया की मां ने अपनी बेटी और पति के लिए प्यार से बुता नो काकुनी नाम की एक डिश तैयार की थी. शायद किसी ने

भी नहीं सोचा था कि मां के हाथों से बना यह खाना उनके परिवार के लिए उनकी आखिरी निशानी बन जाएगा. खाना बनाने के कुछ ही घंटों बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. मां का अचानक ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया. इस घटना ने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ दिया. लेकिन, मां के अचानक चले जाने के बाद घर में बना वह खाना परिवार के लिए सिर्फ एक डिश नहीं रह गया था.

उसमें मां के हाथों का स्वाद, उनका प्यार और उनकी आखिरी याद जुड़ी हुई थी. बेटी और पिता उस खाने को फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. उन्होंने उस खाने को फ्रीजर में रख दिया.

शायद उनके लिए उसे संभालकर रखना ऐसा था, जैसे मां की आखिरी निशानी को अपने पास सहेज कर रखना. दिन बीतते गए, महीने गुजर गए और देखते ही देखते साल बीत गए, लेकिन मां के हाथों से बना वह आखिरी खाना फ्रीजर में वैसे ही रखा रहा. समय गुजरता गया. दिन महीने बने और महीने सालों में बदल गए, लेकिन फ्रीजर में रखा मां के हाथों से बना वह आखिरी खाना वहीं रहा. पांच साल तक परिवार ने उसे संभालकर रखा, क्योंकि उनके लिए वह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि मां के प्यार और उनके साथ बिताए पलों की आखिरी निशानी बन चुका था.

रिलेशनशिप और हेल्थ से जुड़ा कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दिया.

है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं.

सरसों तेल के टैंक में लगाई डुबकी

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो आते हैं जो खाने-पीने के समान की अनहाइजिनिक को दिखाता है. कभी मिठाई में गंदगी, कभी घर में बने समोसे और कभी सोया चाप में लोटते हुए लोग नजर आते हैं. अब ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बारे में लोग अंदाजा तो लगाते थे कि इसमें मिलावट तो हो सकती है, लेकिन अनहाइजिन नहीं. बात हो रही है सरसो की तेल की. अब इस वीडियो को देखकर लोग हैरान और गुस्से में हैं. वीडियो में युवक सरसों के तेल से भरे बड़े स्टोरेज टैंक में नहाता नजर आ रहा है.

बेंगलुरु की टेक कर्मचारी का छलका दर्द

AI ने बढ़ा दिया वर्कलोड

बेंगलुरु की टेक प्रोफेशनल रुपाली तिवारी का दावा है कि AI आने के बाद 5 की जगह अब 20-25 टास्क मिल रहे हैं. उनका वीडियो वायरल हो गया है.

AI आया तो सबको लगा था काम आसान हो जाएगा. लेकिन बेंगलुरु की एक टेक प्रोफेशनल का दावा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है- उनके मुताबिक AI ने काम आसान करने के बजाय कर्मचारियों पर काम का बोझ कई गुना बढ़ा दिया है. इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए रुपाली तिवारी ने बताया कि

AI टूल्स आने के बाद टेक इंडस्ट्री में मैनेजरों और लीड्स की उम्मीदें आसमान छूने लगी हैं.

अब उन्हें लगता है कि जब AI इतना काम कर रहा है, तो कर्मचारी पहले से कहीं ज्यादा काम आसानी से संभाल सकते हैं. रुपाली ने बताया कि जब शुरुआत में AI का इस्तेमाल शुरू हुआ था, तो कई लोगों को नौकरी जाने का डर सता रहा था. साथ ही काम भी काफी आसान लगने लगा था.

उन्होंने कहा कि जब AI पहली बार आया तो लाइफ काफी आसान लगने लगी थी. लेकिन मन में यह डर भी था कि कहीं हमारी नौकरी ही न चली जाए.लेकिन कुछ समय बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई.

मैनेजरों ने यह मानना शुरू कर दिया कि अगर AI काम आसान कर सकता है, तो कर्मचारियों को पहले से कहीं ज्यादा काम दिया जा सकता है. रुपाली का दावा है कि पहले जहां किसी कर्मचारी को पांच काम दिए जाते थे, वहीं अब 20 से 25 काम दिए जाने लगे हैं.उन्होंने कहा कि अब आप चाहे जितना काम कर लें, वह काफी नहीं है. लोगों को लगता है कि AI तो सब कुछ कर ही रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? उन्होंने अपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्त का उदाहरण भी दिया, जो एक बड़ी कंपनी में एक साथ करीब 10 प्रोजेक्ट संभाल रहा है- खुद कोड लिखता है, खुद रिव्यू करता है और खुद ही डिप्लॉय भी करता है.

लोगों ने भी जताई सहमति

पोस्ट पर कई यूजर्स ने रुपाली की बात से सहमति जताई. एक ने लिखा कि AI ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, लेकिन साथ ही उम्मीदें भी बढ़ा दीं. दूसरे ने लिखा कि जितना ज्यादा AI, उतना ही ज्यादा वर्कलोड. अब सवाल यही उठ रहा है- AI सच में कर्मचारियों का काम कम कर रहा है, या कंपनियों ने इसे ज्यादा आउटपुट निकालने का जरिया बना लिया है?

'महाकाली' के टीजर में छाईं श्रिया रेड्डी

'सलार' की राधा राम मन्नार से महाकाली तक का दमदार सफर

'महाकाली' का टीजर आज जारी कर दिया गया, जिसमें अक्षय खन्ना के साथ ही श्रिया रेड्डी की पहली झलक देखने को मिली। एक्ट्रेस का दमदार अंदाज देखने के बाद लोग जानना चाहते हैं कि श्रिया रेड्डी कौन हैं? बता दें, एक्ट्रेस इससे पहले सुपरहिट 600 करोड़ कमाने वाली फिल्म दे चुकी हैं। भारतीय सिनेमा में अपनी दमदार मौजूदगी और सशक्त अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री श्रिया रेड्डी इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में हैं। प्रशांत नील के निर्देशन में बन रही बहुप्रतीक्षित फिल्म 'महाकाली' के टीजर ने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। जहां एक तरफ इस पौराणिक थ्रिलर फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना 'असुरगुरु शुक्राचार्य' की एक बेहद शक्तिशाली भूमिका में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 'महाकाली' के रूप में श्रिया रेड्डी के प्रचंड और रौद्र रूप ने दर्शकों का ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया है। फिल्म के हालिया जारी टीजर में अक्षय खन्ना असुरों के अस्तित्व और 14 लोकों के अधिकारों के लिए संवाद बोलते दिखाई देते हैं। उनका लुक और अभिनय काफी प्रभावशाली है। हालांकि टीजर के अंतिम क्षणों में जैसे ही श्रिया रेड्डी का महाकाली रूप स्क्रीन पर आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। टीजर के 2 मिनट 42 सेकंड पर दिखने वाला वह दृश्य, जहां महाकाली की आंखों में एक ओर वात्सल्य और ममता है तो दूसरी ओर भयंकर क्रोध का भाव है, जो दर्शकों को अचंभित कर रहा है। सोशल मीडिया पर दर्शक खुलकर कह रहे हैं कि उस एक सीन में श्रिया रेड्डी का औरा और अभिनय का स्तर दिग्गज अभिनेता अक्षय खन्ना पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब श्रिया रेड्डी ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से किसी बड़े सितारे को कड़ी टक्कर दी हो। इससे पहले प्रशांत नील की ही 600 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सलार: पार्ट 1 - सीजफायर' में उन्होंने 'राधा राम मन्नार' का आइकॉनिक किरदार निभाया था। पृथ्वीराज सुकुमारन की बहन के रूप में उनके उस कठोर अभिनय की तुलना ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' की शिवगामी देवी (राम्या कृष्णन) के किरदार से की गई थी। कई दृश्यों में श्रिया का प्रभुत्व प्रभास जैसे बड़े सुपरस्टार के सामने भी पूरी तरह से कायम रहा, जिसने उन्हें पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई। इस फिल्म की कमाई पर नजर डाले तो फिल्म ने दुनिया भर में 617 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। श्रिया रेड्डी का सिनेमा तक पहुंचने का सफर काफी दिलचस्प रहा है। 28 नवंबर 1982 को जन्मी श्रिया एक प्रतिष्ठित खेल पृष्ठभूमि से आती हैं। वह पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर भरत रेड्डी की बेटी हैं। भरत रेड्डी ने 1978 से 1981 के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और वह भारत के प्रमुख विकेटकीपर्स में गिने जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने दिनेश कार्तिक जैसे मशहूर भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज को भी शुरुआती दिनों में कोचिंग दी है। श्रिया का जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुड शेफर्ड स्कूल से पूरी करने के बाद चेन्नई के प्रतिष्ठित एथिराज कॉलेज से पढ़ाई की। अभिनय की दुनिया में आने से पहले श्रिया एक बेहद लोकप्रिय वीडियो जॉकी और रेडियो जॉकी के रूप में काम कर चुकी थीं। उनकी बेबाक आवाज और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उन्हें टीवी की दुनिया में पहचान मिली। उनके निजी जीवन की बात करें तो श्रिया रेड्डी का संबंध दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक बड़े फिल्मी परिवार से भी है। उन्होंने साल 2008 में अभिनेता और तमिल फिल्मों के जाने-माने निर्माता विक्रम कृष्णा से शादी की, जो कि दक्षिण भारतीय एक्शन स्टार विशाल के बड़े भाई हैं।

जिस कॉलेज में कभी पढ़े थे, वहीं शिक्षक बने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, छात्रों को पढ़ाया लोकतंत्र का पाठ

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ के अपने पुराने कॉलेज कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज पहुंचकर छात्र जीवन की यादें ताजा कीं।उन्होंने कक्षा 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों से संवाद कर मतदान, मताधिकार, चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका समझाई।ज्ञानेश कुमार ने छात्रों से जिम्मेदार नागरिक बनने और भविष्य के पहली बार मतदाता के रूप में अपने अधिकार व कर्तव्यों को समझने की अपील की।

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। सोमवार को वह शहर के उस कॉलेज में पहुंचे, जहां कभी खुद स्टूडेंट थे। ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ के कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज से पढ़ाई की है। सोमवार को जब वह कॉलेज पहुंचे तो बीते दिनों की यादें ताजा हो गईं। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार ज्ञानेश कुमार शिक्षक की भूमिका में नजर आए। कॉलेज में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और उन्हें लोकतंत्र, चुनाव, मताधिकार सहित जिम्मेदार नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया। अपने छात्र जीवन की यादों को साझा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कॉलेज ने उन्हें केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन, चुनौतियों से लड़ने का साहस और सही विचारों को आत्मसात करने की क्षमता भी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि स्कूल और कॉलेज का समय जीवन का ऐसा दौर होता है, जब अच्छे शिक्षक, माहौल और अनुभव व्यक्तित्व को गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि यहां के शिक्षकों ने उन्हें बहुत कुछ दिया और विद्यालय से मिली सीख आगे चलकर उनके जीवन में बेहद काम आई। विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्हें अपने विद्यालय से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला, उसी तरह आज के विद्यार्थियों को भी अपने शिक्षकों और कॉलेज के माहौल से मिलने वाली सीख को ग्रहण करना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने छात्रों को लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मतदान महज एक अधिकार नहीं, बल्कि देश के भविष्य के निर्माण में भागीदारी का महत्वपूर्ण जरिया है। जागरूक मतदाता ही मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला रखते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने मताधिकार के साथ-साथ उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित किया। संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने चुनाव प्रक्रिया, मतदाता बनने की पात्रता, मतदान और निष्पक्ष चुनाव से जुड़े कई सवाल पूछे। ज्ञानेश कुमार ने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में युवा पीढ़ी की सक्रिय और जिम्मेदार भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यह समय खास है। इनमें से कई विद्यार्थी आने वाले समय में पहली बार मतदान करेंगे। ऐसे में उन्हें अभी से अपने अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना चाहिए। कॉल्विन तालुकदार्स कॉलेज पहुंचने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उनका बहुत पुराना और गहरा नाता है। यहीं से शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़े। लंबे समय बाद अपने विद्यालय लौटकर विद्यार्थियों के बीच आना उनके लिए विशेष अनुभव रहा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में अलग-अलग दौर आते हैं। आज वे जिस दौर से गुजर रहे हैं, वह उनके व्यक्तित्व और भविष्य को आकार देने वाला समय है।

जीबी पंत पॉलीटेक्निक छात्रावास में बदहाल सुविधाओं से छात्र परेशान

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

समाज कल्याण विभाग से संचालित मोहान रोड की राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पॉलीटेक्निक के छात्रावासों के ज्यादातर कमरों की खिड़कियों के ऊपर का कांच गायब और जाली तक नहीं लगी है। परिसर में झाड़-झंकाड़ उगी है। जहरीले जीव-जंतुओं के घुसने का डर, गंदगी और मच्छरों का प्रकोप छात्रों को बीमार कर रहा है। जीबी पंत पॉलीटेक्निक में सिर्फ छात्रों के लिए ही छात्रावास की व्यवस्था है। परिसर में सिद्धार्थ और डॉ. आंबेडकर दो छात्रावास हैं। इनमें 150 के करीब छात्रों के रहने की व्यवस्था है। दो मंजिला भवन में बने कमरों में रहने वाले छात्रों को बेड तो मिल गया लेकिन खिड़कियों के ऊपर कांच या जाली तक नहीं लगवाई गई। इससे कोई भी जीव-जंतु अंदर आ सकता है। गंदगी की वजह से मच्छरों का प्रकोप इस कदर है कि हॉस्टल में रहने वाले छात्र आए दिन बुखार की चपेट में आ जाते हैं। सुशील, राहुल व अन्य छात्रों ने बताया कि इस संबंध में भी कई प्रार्थना पत्र दिए गए लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। सिद्धार्थ छात्रावास में रहने वाले मंगला प्रसाद और अन्य छात्रों ने बताया कि पेयजल के नाम पर अभी कुछ दिन पहले ही दूसरे तल पर वाटर फ्रीजर लगाया गया है। इसमें टंकी काफी कम क्षमता की रखी गई। अक्सर पानी खत्म हो जाता है। कभी-कभार रात के समय कॉलेज गेट के समीप लगे फ्रीजर से पानी लाना पड़ता है। सिद्धार्थ हॉस्टल के पहले तल के स्नानघर-शौचालय में छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। छत की सरिया नजर आने लगी है। छत से पानी भी टपकता है। कुछ दिन पहले एक छात्र चोटिल होने से भी बचा। कई शौचालयों में दरवाजा तो लगा लेकिन पल्ला गायब है।

यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ IT एक्ट और BNS की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

दिल्ली की सियासत और कानूनी गलियारों में उस वक्त हलचल बढ़ गई, जब यूट्यूब शो 'साप्ताहिक बकैती' में दिए गए एक बयान को लेकर यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत पर नॉर्थ एवेन्यू थाने में SC/ST एक्ट, IT एक्ट और BNS की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। मामला अजीत भारती के 22 अगस्त 2026 को प्रसारित वीडियो "SB79: Reservation Hatao Andolan Nautanki & More | Saptahik Bakaiti" से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीडियो के दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद तथा डॉ. बीआर अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। FIR दर्ज होने के बाद अजीत भारती ने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके परिवार, खासकर उनकी मां और बहन को लेकर की गई कथित अश्लील टिप्पणियों के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, " मां-बहन पर टिप्पणी सुनकर चुप कैसे रहता?" मामला दर्ज होने के बाद अजीत भारती ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट के जरिए अपनी सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि उनके वीडियो पर किसी व्यक्ति ने उनकी मां और बहन को लेकर बेहद अमर्यादित टिप्पणी की थी। भारती का कहना है कि ऐसे व्यक्तिगत और गंभीर हमले के बाद चुप रहना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपनी ओर से किसी जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उनके मुताबिक, पूरे मामले को संदर्भ से अलग करके देखा जा रहा है।अजीत भारती ने अपने बयान में कहा कि उन्हें

पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। उन्होंने दावा किया कि FIR में लगाई गई धाराएं अदालत में टिक नहीं पाएंगी और पुलिस पर दबाव में कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह कानून का पालन करेंगे और पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अजीत भारती ने अपने बयान में अपने सैनिक स्कूल में पढ़ने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई से उनका मनोबल आसानी से नहीं टूटने वाला। उन्होंने अपने समर्थकों और सवर्ण समाज के लोगों से भी सवाल किया कि क्या किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के दबाव में परिवार की महिलाओं के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को सहन कर लेना चाहिए।

दिव्या मिश्रा मर्डर केस में नया मोड़

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

दिव्या मिश्रा मर्डर केस में परिवार ने पति मानस वाजपेयी से एलिमनी के रूप में 1.5 करोड़ रुपये की मांग करने वाले दावों को खारिज किया है। परिवार वालों का कहना है कि स्त्रीधन और एलिमनी में अंतर होता है। दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सवाल खड़ा किया कि एक बैंक कर्मचारी होने के बावजूद मानस को इतने हथियार कहां से मिले। बता दें कि 20 अगस्त को बैंक अधिकारी दिव्या मिश्रा की उनके पति मानस वाजपेयी ने पहले गोली मारकर हत्या की उसके बाद अपनी बहन और खुद की भी जान ले ली थी। पुलिस इस हत्याकांड से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया में चल रहे दावों को गलत बताया जिसमें दावा किया गया गया था कि दिव्या मिश्रा ने पति मानस से एलिमनी के रूप में 1.5 करोड़ रुपये की मांग की थी। प्रज्ञा मिश्रा ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपये की रकम को गलत तरीके से गुजारा भत्ता (एलिमनी) बताया गया है। उन्होंने समझाया कि स्त्रीधन महिला का अधिकार होता है जबकि स्थायी गुजारा भत्ता (एलिमनी) एक अलग कानूनी राहत है। उन्होंने दावा किया कि दिव्या की तलाक प्रक्रिया अभी केवल काउंसलिंग के चरण तक ही पहुंची थी। परिवार ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें कार्यवाही में मांगे गए 'स्त्रीधन' की सटीक रकम की जानकारी नहीं है और न ही उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये के दावे के कोई दस्तावेजी सबूत दिए हैं। पुलिस वारदात से पहले की परिस्थितियों को समझने के लिए वैवाहिक विवाद और लेन-देन से जुड़े मामलों की छानबीन कर रही है। मानस के आवास से दो पिस्तौल और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच से यह तय होगा कि किस वारदात में किस हथियार का इस्तेमाल हुआ था। वहीं, दिव्या की बहन ने सवाल खड़ा किया कि एक बैंक कर्मचारी होने के बावजूद मानस को इतने हथियार कहां से मिले। पुलिस सभी एविडेंस को लेकर जांच कर रही है।

जनता दर्शन में सीतापुर की पूनम देवी ने गोपालन के जरिए आत्मनिर्भर बनने की इच्छा जताई

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

सीतापुर के गुरुदेव नगर हरगांव की रहने वाली पूनम देवी 'जनता दर्शन' में मुख्यमंत्री से मिलीं और गोपालन की अभिलाषा बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल उनकी मांगों पर विचार करते हुए अपर मुख्य सचिव (पशुधन) को निर्देश दिया कि इन्हें निराश्रित गाय उपलब्ध कराई जाए और नियमानुसार योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाए। वहीं एक दिव्यांग ने अवैध कब्जे की भी शिकायत की, जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच कराकर निराकरण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री को दिए प्रार्थना पत्र में पूनम देवी ने लिखा कि वह गोपालन करके आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। अभी उनके पास 5 गाय हैं और अन्य गोमाता को रखने के लिए पर्याप्त जगह भी है। ऐसे में उन्हें और भी गाय दिला दी जाएं, जिससे वे दूध आदि की बिक्री कर परिवार को समृद्ध करेंगी। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अपर मुख्य सचिव (पशुधन) को निर्देश दिया कि इन्हें निराश्रित गाय उपलब्ध कराई जाए और मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गोवंश की देखभाल के लिए आर्थिक सहायता भी दिलाई जाए। 'जनता दर्शन' में मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी का हालचाल जाना, फिर सभी की समस्याएं भी पूछीं। पूनम का प्रार्थना पत्र पढ़कर मुख्यमंत्री ने उनकी हौसलाअफजाई भी की। मुख्यमंत्री ने पूनम से कहा कि हम आपको सरकार की तरफ से नियमानुसार योजनाओं का लाभ दिलाएंगे।

उन्नाव की 6148 रसोइयों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मानदेय बढ़ा; कैशलेस इलाज और ₹2 लाख सामाजिक सुरक्षा का लाभ

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में भोजन बनाने वाली 6148 रसोईयों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा का लाभ मिलेगा। अब रसोईया में खाना बनाने वाली महिलाओं को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रतिमाह मिलने वाले मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। इस संबंध में विकास भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें जिलाधिकारी घनश्याम मीना, जिला पंचायत अध्यक्षा शकुन सिंह ने जिले की रसोईयों को कैशलेश चिकित्सा कार्ड का वितरण किया। प्रतीक के रूप में बढ़े हुए मानदेय की चेक भी प्रदान की गई। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले अटवा मोहाल ओसिया प्राथमिक विद्यालय की रसोईया खिलाना को अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता की मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में के विकास भवन में बेसिक शिक्षा परिषद सबसे संचालित विद्यालयों में भोजन बनाने वाली रसोइयों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज का दिन रसोइयों के लिए खास दिन था। जब उनकी बहु प्रतिक्षित मांगों को पूरा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रसोइयों के मानदेय दो हजार से बढ़ाकर तीन हजार करने की घोषणा की है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने कहा कि खाना बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। भोजन में डाली जाने वाली सामग्री का अनुपात सही हो। मिड डे मील और आवासीय विद्यालय में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।IB जिला पंचायत अध्यक्षा शकुन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन के पहले बहनों को बड़ा उपहार दिया है। एक साथ चार योजनाओं का लाभ दिया गया है। जो आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में खाना बनाने वाली रसोइयों का मानदेय दो हजार से बढ़ाकर तीन हजार गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई। अब रसोईयों को कैशलेस चिकित्सा का लाभ भी मिलेगा। काम करते समय दुर्घटना होने पर 2 लाख की सामाजिक सुरक्षा देने की भी घोषणा की गई है। साड़ी के लिए 500 सौ रुपए मिलने वाला भत्ता अब एक हजार रुपए कर दिया गया है। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत गाकर लोगों का मन मोहा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, जिला विकास अधिकारी शैलेश पांडेय सहित अन्य संबंधित अधिकारी, बडी संख्या में रसोइया आदि मौजूद थी।

के काजीखेड़ा गांव में संपत्ति और नशेबाजी को लेकर हुए विवाद में हत्या

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के पुरवा कोतवाली क्षेत्र के काजीखेड़ा गांव में संपत्ति और नशेबाजी को लेकर हुए विवाद में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की हंसिए से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई किशन लोधी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार दोपहर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मृतक की पहचान दिलीप लोधी (24) के रूप में हुई है, जो चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था। परिजनों के अनुसार, परिवार में एक बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। रविवार रात दिलीप का दूसरे नंबर के भाई किशन लोधी से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच नशेबाजी को लेकर भी कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर किशन ने हंसिया उठाकर दिलीप पर हमला कर दिया। हंसिए के हमले से दिलीप गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। घटना के बाद परिजनों और आसपास के लोगों ने घायल दिलीप को आनन-फानन में सीएचसी पुरवा पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुरवा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। पुलिस ने आरोपी किशन लोधी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सोमवार को पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे दोपहर करीब तीन बजे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोतवाली प्रभारी भुवन सिंह मौर्य ने बताया कि बंटवारे को लेकर भाइयों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी किशन को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले में तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौशालाओं में अव्यवस्थाओं और गोवंशों की देखरेख में लापरवाही का आरोप लगाते हुए गौ सेवक शिवम रावत कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के जिले की गौशालाओं में अव्यवस्थाओं और गोवंशों की देखरेख में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सोमवार शाम गौ सेवक शिवम रावत कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने गौशालाओं में गोवंशों को दिए जाने वाले चारे की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए और जिम्मेदार अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की। गौ सेवक शिवम रावत ने आरोप लगाया कि गौशालाओं में गोवंशों को ऐसा चारा खिलाया जा रहा है, जिसमें घुन और कीड़े पड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि चारे की गुणवत्ता की उचित जांच नहीं की जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने कई क्षेत्रों में अन्ना गोवंशों के साथ अनहोनी की घटनाएं होने का भी आरोप लगाया। सोमवार शाम करीब साढ़े चार बजे कलेक्ट्रेट में गौ सेवक के धरने की सूचना अधिकारियों को मिली। इसके बाद एसडीएम सदर राजेश विश्वकर्मा मौके पर पहुंचे और शिवम रावत से बातचीत की। शिवम रावत ने एसडीएम के सामने गौशालाओं की व्यवस्थाओं और गोवंशों की स्थिति से जुड़ी अपनी शिकायतें विस्तार से रखीं। गौ सेवक ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (सीवीओ), ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और ग्राम प्रधानों पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि गौशालाओं में गोवंशों की स्थिति और उपलब्ध व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी नहीं होने के कारण समस्याएं बनी हुई हैं। उन्होंने अन्ना गोवंशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में जांच कर कार्रवाई की मांग की।

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पांच स्थानों पर सड़क दब गई

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे (एनई-6) पर सफर अब सुरक्षित नहीं रह गया है। लोकार्पण के एक माह दस दिन बाद भी रोजाना सड़क धंसने और उखड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में रविवार को कानपुर से लखनऊ के बीच भारी वाहन लेन पर पांच स्थानों पर सड़क दब गई। वहीं बोल्डर भी टूट गया है। अंडरपास के पास बनी नाली 24 घंटे भी नहीं चल पाई है। लगातार किरकिरी झेल रहे एक्सप्रेसवे की कार्यदायी संस्था पीएनसी ने दिन के साथ अब रात में भी मरम्मत शुरू कराई है। इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 13 जुलाई को 4200 करोड़ रुपये की लागत से हुआ था। समारोह में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। 14 जुलाई से इस पर वाहनों का आवागमन शुरू हुआ था। यातायात शुरू होते ही एक्सप्रेसवे टूटने और धंसने लगा। एक माह दस दिन बीत जाने के बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब एक्सप्रेसवे क्षतिग्रस्त न हुआ हो। अंडरपास के पास बनी नाली भी 24 घंटे नहीं चल पाई और मिट्टी बह जाने से रेन कट बन गए। रविवार को किलोमीटर 60.5 से 60.3 और 60 से 59.5 तक अड़ेरुवा गांव के पास सड़क धंसी। दुर्जनखेड़ा गांव के पास किलोमीटर 59.3 से 58.5 तक भी सड़क दबी। तियरिया गांव के पास किलोमीटर 57.9 से 58.8 तक भी क्षति हुई। किलोमीटर 48.8 पर तौरा गांव के पास बीच में रखा बोल्डर टूटा मिला। कोरारी टोल प्लाजा की तरफ कानपुर-लखनऊ लेन पर किलोमीटर संख्या 65 पर बने उन्नाव-लालगंज हाईवे के अंडरपास के पास करीब दस मीटर सड़क में नाली (व्हील ट्रैक) बनने से वाहन अनियंत्रित होने लगे थे। समस्या सामने आने पर निर्माण एजेंसी पीएनसी ने शनिवार को आनन-फानन मरम्मत कराई थी। वहीं नाली रविवार को ही उखड़ गई। बिछाया गया डामर बह गया। वहीं किमी संख्या 69.9 पर आटा गांव के सामने बारिश के पानी से सड़क किनारे की मिट्टी बह जाने से रेन कट बन गया। लोकार्पण के बाद से रोजाना धंस रहे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की खामियों पर पर्दा डालने के लिए निर्माण एजेंसी ने अब रात के समय पैचवर्क व अन्य मरम्मत कार्य शुरू कराया है। शनिवार रात के अंधेरे में मशीनों के जरिए किमी 63.1 से लेकर 62.5 के बीच कानपुर-लखनऊ लेन पर डामर की नई लेयर डालने व अन्य मरम्मत कार्य किया गया।

एक कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना राष्ट्रगान को बीच में ही छोड़कर चले गए

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में शनिवार को उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई, जब यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना गार्ड ऑफ ऑनर के बाद तब सलामी मंच से उतर गए, जब राष्ट्रगान चल रहा था। इस पूरे वाकया का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि महाना उतरकर कान के पास कुछ ठीक करते हैं। कानपुर की महाराजपुर सीट से विधायक और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शनिवार को उन्नाव के पूरन नगर के एक स्कूल में प्रधानाचार्य परिषद के अधिवेशन और संगोष्ठी में पहुंचे थे। कार्यक्रम में परंपगरात रूप से प्रोटोकॉल के तहत महाना को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये खत्म होते ही तुरंत राष्ट्रगान शुरू हो गया। वीडियो में देखा जा रहा है कि महाना सलामी मंच से अचानक पीछे की तरफ मुड़े और कान में कुछ ठीक करते हुए उतर गए। कुछ दूरी पर खड़े समर्थक उनके साथ आ गए और पैर छूने लगे। इस दौरान भी राष्ट्रगान बज रहा था और महाना गाड़ी में बैठकर चले गए। कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाना ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में करोड़ों लोग संघर्ष में खड़े थे। मंदिर सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। मंदिर के लिए दी गई राशि भगवान के चरणों में समर्पण है। समर्पण राशि वापस मांगने की बात आस्थावानों को आहत करने वाली है। सदन में विपक्ष को मैंने कई बार हाथ जोड़ करके अपनी बात रखने के लिए कहा, लेकिन बात सुनने को तैयार नहीं हुए। जेन जी आंदोलन पर कहा कि बच्चों के हित के लिए मां-बाप सोचते हैं। किसी व्यवस्था को अच्छा या खराब कहने से पहले परिस्थितियों को समझना जरूरी होता है। सुधार की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन संस्कार और सीमा में रहकर समाज और सरकार आने वाले मुद्दों को मिलकर सुलझा लेंगे।

खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में रक्षाबंधन से पहले खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। सफीपुर और बांगरमऊ क्षेत्र में हुई छापेमारी के दौरान टीम ने 1.14 लाख रुपये से अधिक कीमत की खाद्य सामग्री नष्ट कराई, जबकि 8 नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए। कार्रवाई के दौरान सफीपुर में बिना लाइसेंस खोया बेचने का मामला सामने आया। वहीं बांगरमऊ की एक डेयरी में खोया तैयार करने के दौरान सोडियम सल्फाइट के इस्तेमाल की जानकारी मिली। विभाग की कार्रवाई के बाद डेयरी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। सफीपुर के मुन्नू खेड़ा में खाद्य सुरक्षा टीम ने खोया विक्रेता बृजेश यादव के प्रतिष्ठान की जांच की। यहां खाद्य कारोबार के लिए आवश्यक पंजीकरण या लाइसेंस नहीं मिला। टीम ने खोया के दो नमूने लिए। मौके पर मौजूद 14 किलो खोया और 3 किलो अपमिश्रक को नष्ट कराया गया। इसके बाद प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया। सबसे बड़ी कार्रवाई बांगरमऊ क्षेत्र के गुलजारपुर सलेमपुर (काटा) स्थित मेसर्स सागर डेयरी में हुई। निरीक्षण के दौरान खोया तैयार करने में सोडियम सल्फाइट के इस्तेमाल की जानकारी सामने आई। टीम ने खोया, दूध, सोडियम सल्फाइट और घी के कुल 6 नमूने लिए। मौके पर 290 किलो खोया और 360 लीटर दूध नष्ट कराया गया। वहीं 8 किलो सोडियम सल्फाइट और 15 किलो घी जब्त किया गया। विभाग ने डेयरी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए आगामी आदेश तक कारखाना बंद रखने का नोटिस जारी किया। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II प्रियंका सिंह ने बताया कि दोनों स्थानों से लिए गए सभी 8 नमूने राजकीय प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

UP Election 2027: सीट बंटवारे पर घमासान

NDA में 162 सीटों का दावा तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने बढ़ाया दबाव

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर NDA और इंडिया गठबंधन, दोनों में सियासी खींचतान तेज होती दिख रही है।अखिलेश यादव ने NDA में सहयोगी दलों के लिए 162 सीटों का दावा किया है, जबकि कांग्रेस सपा से सम्मानजनक और बराबरी के आधार पर ज्यादा सीटें मांग रही है।जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के बयानों के बाद गठबंधन की राजनीति और गरमा गई है, जिससे 2027 का सीट गणित बेहद दिलचस्प हो गया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भाजपा को अपने सहयोगी दलों के लिए 162 सीटें छोड़नी पड़ेंगी। वहीं, कांग्रेस ने भी सपा पर दबाव बढ़ाते हुए बराबरी और सम्मानजनक सीट बंटवारे की मांग तेज कर दी है। दूसरी ओर, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर के बयानों से गठबंधन की सियासत और गरमा गई है। ऐसे में चुनाव से पहले NDA और इंडिया गठबंधन, दोनों में सीटों का गणित बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा को अपने सहयोगी दलों सुभासपा, रालोद, निषाद पार्टी और अपना दल (एस) के लिए कुल 162 सीटें छोड़नी पड़ेंगी। सपा के इस दावे को NDA के भीतर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सपा की कोशिश है कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर महत्वाकांक्षा और खींचतान सामने आए। अगर सहयोगी दल ज्यादा सीटों की मांग करते हैं तो भाजपा के लिए सीटों का बंटवारा तय करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक तरफ सपा NDA के भीतर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने ही गठबंधन में सीटों को लेकर रुख कड़ा कर लिया है। कांग्रेस अब सपा के साथ एकतरफा सीट बंटवारे के पक्ष में नहीं है। पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर सर्वे करा रही है और जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसका प्रभाव बढ़ा है और पिछले चुनाव की तुलना में उसकी स्थिति मजबूत हुई है। कांग्रेस की सबसे अहम दलील यह है कि सीटों का बंटवारा केवल साल 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को भी आधार बनाने की बात कह रही है। संसद और छात्र आंदोलनों में सक्रियता के बाद कांग्रेस अपने बढ़े राजनीतिक प्रभाव को सीटों की मांग का आधार बना रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सपा से पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें मांग सकती है। NDA की तरफ से सुभासपा प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहले ही सपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब केंद्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा पर सहयोगी दलों को कमतर आंकने का आरोप लगाया है। जयंत के बयान पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सपा के साथ अपने पहले के दो गठबंधनों के अनुभव को कटु बताया और राष्ट्रीय लोकदल के बयान से सहमति जताई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 376 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सहयोगी दलों के लिए 27 सीटें छोड़ी थीं। भाजपा ने 255 सीटें जीती थीं। अपना दल ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें जीतीं, जबकि निषाद पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की। विपक्ष में सपा ने रालोद और अन्य दलों के साथ गठबंधन किया था। सपा ने 111 सीटें जीती थीं। रालोद ने 33 सीटों पर चुनाव लड़कर 8 सीटें जीतीं, जबकि सुभासपा ने 19 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अपना दल कमेरावादी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़कर एक सीट जीती थी। सुभासपा और रालोद भाजपा के साथ हैं, जबकि अपना दल कमेरावादी सपा के साथ बना हुआ है। कांग्रेस और सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ चुनाव लड़ा था और अब फिर गठबंधन में आगे बढ़ने की तैयारी है। 2022 में कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। बसपा ने सभी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन उसे भी केवल एक सीट पर सफलता मिली थी। ऐसे में 2027 से पहले सीटों का बंटवारा दोनों गठबंधनों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

कांग्रेस की बैठक में मछली परोसे जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया

अयोध्या के तरुन इलाके में रविवार को स्थानीय निषाद समुदाय की एक राजनीतिक बैठक में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत के लिए मछली की दावत का आयोजन किया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें एक मैरिज लॉन में मछली पकाई जा रही थी। इस पर तुरंत राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सावन के महीने में मछली परोसकर उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यह विवाद इसलिए भी अहम हो गया क्योंकि राय ने उसी दिन हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था और बाद में राम मंदिर में पूजा-अर्चना की थी, जिसके बाद वे लगभग 38 किलोमीटर दूर तरुन गए थे। अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री आलोचना कर रहे हैं; क्या उनके पास कोई फ़ोटो है? अगर वे कोई तस्वीर दिखा सकें, तो मैं तुरंत इस्तीफा देने को तैयार हूँ। निषाद समाज ने मुझे कल अयोध्या में एक कार्यक्रम में बुलाया था। अगर वहाँ मछली तैयार की जा रही थी, तो यह उनकी बात थी। मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ और वापस आ गया। भारी बारिश की वजह से भी मीटिंग पर असर पड़ा। वीडियो सामने आने और मामला सुर्खियों में छाने के बाद, राय मीडिया से बात किए बिना ही वहां से चले गए। बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि सावन के महीने में बड़ी संख्या में हिंदू भगवान शिव की पूजा-अर्चना में लीन रहते हैं। ऐसे समय में मछली की दावत का आयोजन करना कांग्रेस की हिंदू-विरोधी मानसिकता का खुला प्रदर्शन है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में मंदिरों के दर्शन करने के बाद ऐसी घटना में शामिल होना, जहां मछली परोसी गई, कांग्रेस पार्टी के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस घटना को "बेहद निंदनीय और अक्षम्य" करार दिया और मांग की कि कांग्रेस संतों और भक्तों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।

सड़कों की बदहाली पर जेन अल्फा का आक्रोश

उत्तर प्रदेश के महोबा में जेन अल्फा अब अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रशासन के सामने आवाज उठाने लगा है। यहां के सैकड़ों बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बच्चों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं भी मौजूद रहीं। जेन अल्फा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर गांव की खस्ताहाल सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त कर पक्की सड़क निर्माण की मांग की। इसी दौरान बीएसए ने तत्काल कदम उठाते हुए बच्चों से गांव चलने के लिए कहा, ताकि वे खुद देख सकें कि सड़क का हाल क्या है।कागजों में दुरुस्त सड़क, जमीन पर कीचड़ और दलदल बच्चों ने अपने गांव की बदहाल सड़कों की हकीकत सोमवार को महोबा डीएम के सामने रखी। बच्चों ने बताया कि इलाहीपुरा ग्योड़ी गांव खन्ना मुख्य मार्ग से करीब 500 मीटर अंदर स्थित है। गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है। केवल एक कच्ची पगडंडी है। बारिश के दौरान इस रास्ते पर कीचड़ और जलभराव हो जाता है, जिससे बच्चों को इसी रास्ते से स्कूल आने-जाने में परेशानी होती है। बीमार महिलाओं, बुजुर्गों और प्रसूताओं के लिए भी मुख्य मार्ग तक पहुंचना मुश्किल होता है। ग्राम दिसरापुर बिलवई में हजरत इब्राहिम शहीद दरगाह से रेलवे पटरी तक जाने वाले मार्ग की स्थिति भी बेहद खराब है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पक्की सड़क या खड़ंजा नहीं है और बारिश के बाद रास्ता घुटनों तक कीचड़, मलबे और दलदल में तब्दील हो जाता है।बच्चों ने बताया कि खराब रास्ते के कारण आए दिन बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं। उनके कपड़े, जूते और स्कूल बैग खराब हो जाते हैं, जबकि कई बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं। रास्ते की बदहाली के चलते कुछ अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि आपात स्थिति में 102 और 108 एंबुलेंस सहित अन्य वाहन गांव तक पहुंचने में मुश्किल होती है। गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को चारपाई पर ले जाकर दलदली रास्ता पार कराने की नौबत आ जाती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को राहुल गांधी से बहुत कम उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में, मैं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी का एक बयान पढ़ रहा था। उन्होंने महाराष्ट्र में कहा था कि महिलाओं को मनुस्मृति की बेड़ियों से आज़ाद होकर बाहर आना चाहिए। राहुल गांधी, देश को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन भारत की संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर, देश आपसे लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह होने की उम्मीद करता है। क्या आप भारत की परंपराओं और विरासत की आलोचना करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं? योगी ने यह बात स्वतंत्रता सेनानी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। CM योगी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि आपने भारत के संविधान को बनाए रखने की शपथ ली थी, फिर भी आपको भारत की परंपराओं और विरासत की बुराई करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगता है। जब आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं, तो राज्य को बदनाम और अपमानित करते हैं; जब आप विदेश जाते हैं, तो खुद भारत का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में, आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र-विरोधी तत्वों को बढ़ावा देते हैं। आपकी पार्टी अयोध्या में भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाती है। जहां तक लोकतंत्र के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की बात है, तो देश ने 1975 में इमरजेंसी का काला साया देखा था।